राजद समाचार

आजादी, समानता और भाईचारा

राष्ट्रीय जनता दल का मासिक मुखपत्र

अंक–42 अगस्त, 2025 सहयोग राशि–40 रुपये

चुनाव आयोग का स्याह और सच	
बिहार में अब वोटर अधिकार यात्रा की जंग– गौतम कुणाल	03
वोट की चोरी नहीं, डकैती की जा रही है– तेजस्वी प्रसाद यादव	05
गरीब, कमजोरों के पास सिर्फ वोट है– राहुल गांधी	07
संसद से सड़क तक बगावत– लारैब अकरम	10
बेमिसाल है विपक्ष की यह एकजुटता– उर्मिलेश	11
SIR पर 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की रिपोर्ट– आयुषी/विष्णु नारायण	12
बिहार में वोट बैंक में सेंध लगाने का कुचक्र– तेजपाल सिंह 'तेज'	14
बिगाड़ के डर से ईमान की बात... बोलेंगे जज साहब!– हेमंत कुमार	17
पारदर्शी नहीं है 2024 का लोकसभा चुनाव– रिबोर्न मनीष	18
एस.आई.आर पर सुप्रीम कोर्ट में योगेन्द्र यादव– रणविजय	19
चुनाव-चोरी पर राहुल गांधी का खुलासा– रामशरण जोशी	21
मतदात सूची नहीं, लोकतंत्र का शुद्धिकरण हो- अरुण कुमार त्रिपाठी	23
'वोट चोरी' के नारों के बीच याद आये शेषण– पंकज श्रीवास्तव	25
पठन-पाठन/ अरुंधति राय की किताब 'आजादी'– सिद्धार्थ रामू	27
श्रद्धांजलि/ शिबू सोरेन– विनोद कुमार	30
सुमित चक्रवर्ती– रामसुजान अमर	32
नंदू राम– डॉ. अजय कुमार	33
प्रो. सईद आलम– फिरोज मंसूरी	35
रतन थियम– सलीम आरिफ	36
रिपोर्ट/ बढ़ई न्याय अधिकार महासम्मेलन पर– निर्भय अम्बेडकर	38
कवि का पन्ना/ कर्मानन्द आर्य	40

सम्पादक

अरुण आनंद

सहयोग

लारैब अकरम/ डॉ. दिनेश पाल/ साकिब अशरफी

मंगनीलाल मंडल

प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-01 द्वारा प्रकाशित एवं वितरित

राजद समाचार की ईमेल आईडी

samacharrjd@gmail.com

बैकफुट पर चुनाव आयोग

देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक पैमाने पर फर्जी वोटर जोड़ना, वास्तविक वोटर को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना और वोट गिनती में फर्जीवाड़ा करके जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अपदस्थ करना– यही मुख्य वे काम हैं जिसके कारण भारत का निर्वाचन आयोग इन दिनों चर्चाओं में है। बिहार में आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान उनके इसी हिडेन एजेंडे का हिस्सा है। यह महज मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला भर नहीं है। सच तो यह है कि यह लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार-मताधिकार से गरीबों, वंचितों को बेदखल करने का एनडीए सरकार का फरमान है जिसे आयोग मतदाता सूची शुद्धिकरण की आड़ में कार्यान्वित करना चाहता है। यदि लाखों मतदाता प्रशासनिक लापरवाही से मतदाता सूची से बाहर हो जाएं और वोट शुद्धिकरण के नाम पर फर्जी मतदाता शामिल कर लिये जाएं और आयोग इन गड़बड़ियों को उजागर करने वाले को ही दंडित करने की बोल बोलने लगे और गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर चुप्पी साध जाए तो इसे क्या कहा जाएगा– आयोग का सत्ता समर्पण या देश के प्रति अनुराग?

जिस सीमित समय और तर्क के साथ बिहार में इस सर्वे को संपन्न किया गया, उसमें गलतियां होनी ही थीं। इतनी सीमित अवधि में वोटर कार्ड का सुव्यवस्थित सर्वे नहीं हो सकता था, लेकिन फर्जी ढंग से हड़बोंग मचाकर सर्वे पूरे कर लेने का स्वांग मचाकर कोर्ट को तो संतुष्ट किया ही जा सकता था– बिहार के मामले में यही हुआ। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने सूची जारी की तो वे तमाम गड़बड़िया यथावत नजर आ रही हैं जिनको दूर करने के लिए इस सर्वे का नाटक रचा गया था। इस पूरे अभियान में आयोग ने बिहार से एक भी नये वोटर नहीं जोड़े और एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की सामने आयी जो जिंदा थे और आयोग द्वारा इस सर्वे में जिन्हें मृत मान लिया गया था। 7.89 करोड़ वोटर के घरों तक इतने कम समय में बीएलओ की पहुंच संभव नहीं थी। 7 करोड़ 24 लाख फार्म इतनी सीमित अवधि में भरे जाने संभव

नहीं थे। लेकिन शासकीय दवाब में फर्जी तरीके से इन कामों को अंजाम दिया गया। इसका परिणाम आज इस रूप में आ रहा है कि बिहार से सैकड़ों लोग वोटर सूची से अपदस्थ हैं, हजारों के पते गलत दर्ज किये गये हैं।आयोग ने इस सर्वे अभियान में अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। विपक्ष से शपथ पत्र की धमकी देनेवाले ज्ञानेश कुमार क्या इस बात का शपथ पत्र देंगे कि बिहार में लाखों-करोड़ों लोगों का फर्जी दस्तखत बीएलओ कर्मियों ने किस संवैधानिक नैतिकता की कीमत पर की, मतदाताओं को फार्म भरवाने का एकनॉलेजमेंट क्यों नहीं दिया गया, ऑनलाइन मतदाता सूची ढूंढनी हो या निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी जानकारी– आयोग ने पूरे मामले में गोपनयीता बनाये रखी ताकि उनकी कार्रगुजारियां लोगों की जेहन में न आये। बिहार में वोटर शुद्धिकरण के नाम पर व्यापक पैमाने पर की गई ये गड़बड़ियां कई माध्यामों से सामने आयीं लेकिन आयोग ने इसपर कोई नोटिस नहीं ली। उनका यह रवैया बतलाता है कि उन्होंने किस तरह इस आयोग की साख को बट्टा लगाया है।

बिहार सहित पूरे देश में आज यह बात बहुत शिद्दत से विपक्ष द्वारा उठायी जा रही है कि सत्ता पक्ष निर्वाचन आयोग को मोहरा बनाकर एस.आई.आर के नाम पर फर्जी तरीके से अपने लिये अवैध नये वोटर पैदा कर ले रहा है और जनता द्वारा चुनी गई बहुमत की सरकार को पराजित करने का षड्यंत्र कर रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा फर्जी तरीके से बढ़ाये गए नये वोटरों के कारनामे उजागर हो रहे हैं। उससे यह बात सिद्ध होती दिखाई पड़ रही है कि मतदान में व्यापक तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं। विगत दिनों महाराष्ट्र, दिल्ली, ओड़िशा और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद, यह सवाल राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ने लगा है। इन सभी राज्यों में विपक्ष ने चुनाव आयोग को अपने यहां के वोटिंग पैटर्न और फर्जी मतदान की शिकायतें की हैं जिसपर आयोग चुप है। इससे इन आरोपों की हकीकत सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि वास्तव में निष्पक्ष हो। लेकिन वह निष्पक्ष दिख ही नहीं रही है तो निष्पक्ष साबित कहां से होगा? अभी सीएसडीएस-लोकनीति का ताजा सर्वे भी इस बात की तसदीक करता है कि 2019 से 2024 के बीच चुनाव आयोग के प्रति जनता का भरोसा काफी हद तक कमा है। यदि आयोग ने भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये तो जनता को लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो जाएगा।

भारत का निर्वाचन आयोग जो कभी अपनी निष्पक्षता के लिये जाना जाता था, जिसकी साख की शोहरत दुनिया भर में मकबूल थी– आज बिहार में वोटरों के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रकरण में लगातार सवालों के घेरे में है। उसने यह साबित कर दिया है कि अब वह भारत की स्वायत संस्था नहीं रहा– भाजपा और आर.एस.एस का अनुसंगी संगठन बन गया है। यहां याद आते हैं पूर्व निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषण और एस.वाई कुरैशी। टी.एन. शेषण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'वह भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, भारत सरकार के नहीं।' यह कैसी विडम्बना है कि जिस देश में इतने साहसी, जन हितैषी और संविधान के रास्ते चलने वाले चुनाव आयुक्त बनाये जाने की परंपरा रही हो वहां आज के निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्वाचन आयोग जैसी स्वायत संस्था को भी सरकार की जेबी संस्था बना दिया गया है।

आयोग का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है, लेकिन वह अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन न करके पूरी तरह मोदी सरकार के एजेंडा को लागू करवाने की मशीनरी बन गया है। अबतक यह सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और एनआईए को अपने मुताबिक इस्तेमाल करती आई थी। इन संस्थाओं का काम था कानून व्यवस्था की रक्षा, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार पर नकेल कसना– लेकिन मोदी राज में इनका एकमात्र घोषित उद्देश्य विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने, कमजोर करने और चुनावी राजनीति में सत्ता हड़पने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करना भर रह गया है। पूरे विपक्ष को मोदी ने इन एजेंसियों के माध्यम से जिस तरह से परेशान किया है, वह अभूतपूर्व है।

विपक्षी नेताओं पर छापे, उनपर बेसिरपैर के मुकदमें– इन संस्थाओं की चाबुक से भारत का शायद ही कोई विपक्ष बचा हो। लेकिन जैसे ही विपक्ष का कोई धड़ा भाजपा के साथ हो जाएं तो उनकी सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। भाजपा के द्वारा यहां की एजेंसियों का ऐसा बेशर्म दोहन बतलाता है कि यहां फासीवाद आ गया है, कुछ बचा नहीं है। उन्होंने वह किया है जो भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर वह हथकंडा जो इस देश और संविधान को तार-तार करता हो, यहां के नागरिकों में विभेद पैदा करता हो, संस्थाओं की स्वायतता खत्म करता हो– भाजपा उसे अपनाती रही है। उसका सपना एक ऐसा भारत बनाने का है जहां नफरत और झूठ का प्रोपेगेंडा हो, लोकतंत्र और संविधान न रहे।

लेकिन एस.आई.आर ने उनके इस सपने को पलीता लगा दिया है। हाल के सालों में यह पहली दफा हुआ है कि विपक्ष राष्ट्रीय नैरेटिव को डिक्टेट कर रहा है और भाजपा बैकफुट पर आ गई है। बिहार में तेजस्वी-राहुल की जोड़ी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा ने तो पूरी फिजां ही बदल दी है। बहुत पहले जर्मन कवि बर्तोल्त ब्रेख्त ने कहा था कि 'तानाशाह अपनी सनक में अपनी जनता को ही चुनने की हिमाकत करता है।' चुनाव आयोग का यह कवायद, वोट के अधिकार– जनतंत्र के इसी बुनियादी उसूल को उलटने का कुचक्र है। लेकिन इस बार उनकी यह बाजी उलट गई है।

अरुण आनंद